

348
1038

संख्या: 2 / VII-I / 2018-37(सिडकूल) / 2017

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC),
सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादून: दिनांक: 17 जनवरी, 2018

विषय:- औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेशों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2017 से वर्तमान तक निर्गत किये गये महत्वपूर्ण शासनादेशों को सलंगन कर NIC के माध्यम से website पर upload किये जाने हेतु सलंगन कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया तदनुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

सलंगनक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल),
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादून: दिनांक: 17, अक्टूबर, 2017

विषय:- हेमपुर में स्थित मै० नेपा लि० की 803 एकड़ भूमि को राजस्व अभिलेखों में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुए तदोपरान्त उक्त भूमि सिडकुल के नाम हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हेमपुर में स्थित मै० नेपा लि० की 803 एकड़ भूमि का राजस्व अभिलेखों में पंजीकरण व मुआवजा भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 26.09.2017 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में प्रश्नगत भूमि को औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज किये जाने व तदोपरान्त सम्बन्धित भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही करते हुए मै० नेपा लि० को उक्त भूमि के एवज में रू० 96.67 करोड़ का भुगतान किये जाने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26.09.2017 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय एवं शासन के पत्र संख्या-332/VII-I/2017-426 (उद्योग)/2007, दिनांक 14 जून, 2107 द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में नेपा० लि० को तदनुसार धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीय,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव।

संख्या- ६३१ (1)/VII-I/2017-426 (उद्योग)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड
2. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मै० नेपा लि०, नेपा नगर, मध्य प्रदेश।
5. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादून: दिनांक: 10 नवम्बर, 2017

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) के नियमित सेवारत कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भांति दिनांक 01.01.2016 से सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या-291/XXVII(7)30(8)/2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या-727/सिडकुल/सी०आर/2017, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) के नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सातवां वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त अधिसूचना संख्या-290, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में संलग्न वेतन मैट्रिक्स में प्रति स्थापित वेतन इस प्रतिबन्ध एवं शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस सम्बन्ध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जाएगा।
2. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2017 से नकद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का अवशेष वेतन एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।
3. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) के कार्मिकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०एस०) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/XXVII(7)/30(14)/2017 दिनांक 17.02.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) की सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजना के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की प्रक्रिया गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्स से तैनाती का कार्य लिया जा रहा है ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार नियत मानदेय का भुगतान किया जाय, भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) में स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।

२

—2—


5. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) के कार्मिकों को सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्यय-भार उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और न ही राज्य सरकार से पुनरीक्षित वेतनमान की अन्तर की धनराशि की मांग की जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि० (सिडकुल) द्वारा मितव्ययता सुनिश्चित करते हुए आय हेतु अपने संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
2. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०पत्र संख्या-275/XXVII(10)/2017, दिनांक 01 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीया,
मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव।

संख्या- ~~737~~ (1)/VII-1/2017-30 (सिडकुल)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी-सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव।